

क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रारम्भिक प्ररीक्षा के निष्पादन के आधार पर की जाती है;

(5) छात्रवृत्ति शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक की अवधि के धार्य है;

(6) छात्रवृत्तियों का नवीकरण वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर किया जाता है ।

लिखने की कापियों की कमी

934. श्री नन्द किशोर जर्मा:

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय:

श्री माधवराव सिंधिया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में इस समय स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए लिखने की कापियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों को कापियां ठीक समय पर मिल सकें तथा लिखने की पुस्तिकाओं की बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वे निजी विनिर्माता, जिन्हें कापियां बनाने के लिए उचित दर पर कागज प्राप्त करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, सरकार को निश्चित संख्या में कापियां दे रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द): (क) स्कूल के बच्चों के लिए कापियों की भारी कमी सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) स्कूल के बच्चों को कापियां और पाठ्य पुस्तकें उचित दामों पर उपलब्ध हो जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार के पास, राज्य सरकारों को रियायती सफेद मुद्रण कागज देने का एक कार्यक्रम है।

सरकार ने कापियां तैयार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को जनवरी-मार्च, 1980 की तिमाही के लिए 19517 टन एवं अप्रैल-जून, 1980 की तिमाही के लिए 14,883 टन कागज आबंटित किया है। उत्पादन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कापियों के लिए राज्य सरकारों की कागज संबंधी मांग को पूर्णरूपेण पूरा करना संभव नहीं हो सका है; परन्तु तत्काल और अत्यन्त जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आबंटन कर दिया गया है। कागज प्राप्त करने, अपने पर्यवेक्षण में इसे कापियों में परिवर्तित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहकारी समितिय, स्कूलों और जहां कहीं आवश्यक हो प्राइवेट खुदरा व्यापारियों के माध्यम से इनके वितरित करने के लिए एक केन्द्रीयकृत राज्य एजेंसी आरम्भ करने की भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रबन्ध पर पूरी तरह से निगरानी रखें कि बच्चों को कापियां ठीक समय पर और अधिसूचित दामों पर उपलब्ध हो।

(ग) शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ प्राइवेट निर्माताओं ने राज्य एजेंसियों को निर्धारित संख्या में कापियां मुहैया नहीं की हैं।

(घ) सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी है कि केन्द्रीयकृत राज्य एजेंसी कागज को कापियों में परिवर्तन करने और इनके वितरण पर पूरी निगरानी रखें। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे इस कार्यक्रम का व्यापक रूप से निरीक्षण करें और उन निर्माताओं के विरुद्ध अनिवार्य वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत दंडात्मक कार्रवाई करें जो समय पर या पूरी मात्रा में कापियां नुहैया नहीं करते।

Study of Garo Hills in Meghalaya by I.C.A.R.

935. SHRI P. A. SANGAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Indian Council of Agricultural Research has made any